

कमलनाथ-सिंधिया का दबदबा बरकरार

14वीं लोकसभा की तरह 15वीं लोकसभा में फिलहाल मध्यप्रदेश से चार मंत्री ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में नजर आएंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले लोकसभा के दो और राज्यसभा के दो सांसदों को मंत्रीपद से

नवाजा गया था तो इस बार चारों लोकसभा के सदस्य हैं और इनमें दो युवा और दो वरिष्ठ व अनुभवी हैं। पूर्व में मनमोहन सिंह ने राज्यसभा सदस्य सुरेश पचौरी को बतौर राज्यमंत्री शामिल किया था, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपने के बाद उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। बाद में पचौरी की जगह ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यमंत्री बनाया गया था। इस बार राज्यसभा के सदस्य के तौर पर अर्जुन सिंह को मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला। यानी संख्या के

हिसाब से चार मंत्री पहले थे तो इस बार भी उतने ही हैं। जातिगत आधार पर कांग्रेस ने क्षत्रिय नेता के तौर पर अर्जुन सिंह की जगह पिछड़े वर्ग के नेता अरुण यादव को प्राथमिकता दी। अर्जुन सिंह को राज्यपाल बनाए जाने की चर्चा है तो क्षत्रिय नेता के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह संगठन की राजनीति में उत्तरप्रदेश के प्रभारी रहते एक बड़े नेता के तौर पर कांग्रेस में उभरे हैं। हंसराज भारद्वाज भी मध्यप्रदेश से राज्यसभा के सदस्य रहते केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, लेकिन अब वे हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हें भी इस बार मौका नहीं मिला है। राज्य में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कोशिश कांग्रेस ने की, लेकिन बुंदेलखंड और विंध्य से कांग्रेस ने किसी को मौका नहीं दिया, जबकि कांग्रेस के वोट बैंक में संघ लगाती आ रही बसपा के प्रभाव वाले विंध्य क्षेत्र से पार्टी के पास शहडोल की सांसद राजेश नंदिनी सिंह महिला और आदिवासी चेहरे के तौर पर एक विकल्प था, जो पूर्व मंत्री दलबीर सिंह की पत्नी हैं। विंध्य के रीवा संभाग में कांग्रेस की लाज शहडोल ने ही बचाई थी, जबकि अर्जुन सिंह की पुत्री वीणा सिंह की सीधी से निर्दलीय उम्मीदवारी ने कांग्रेस को पराजित करने में अहम भूमिका निभाई, वहीं कांग्रेस रीवा में बसपा और सतना में भाजपा के हाथों हार गई। बुंदेलखंड की चार सीटों पर कांग्रेस का सूपडा भाजपा ने भले ही साफ कर दिया हो, लेकिन इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद सत्यव्रत चतुर्वेदी एक दावेदार के रूप में थे, जिनके पास न सिर्फ लोकसभा बल्कि राज्यसभा के साथ साथ संगठन का भी अनुभव है। महाकौशल से कांग्रेस के हाई प्रोफाइल नेता कमलनाथ को पहले मंत्रिमंडल विस्तार में ही मनमोहन सिंह ने जगह दे दी थी तो मालवा का नेतृत्व करने वाले कांतिलाल भूरिया की पदोन्नति कर कांग्रेस ने क्षेत्र के साथ-साथ आदिवासी वोट बैंक में अपनी पैठ और बढ़ाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। भूरिया



की पदोन्नति में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की विशेष रुचि ने भी गुल खिलाए। निमाड से नया चेहरा अरुण यादव को कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुभाष यादव के पुत्र होने का फायदा मिला तो उनकी नियुक्ति को राहुल गांधी की युवा ब्रिगेड की आगामी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। मालवानिमाड क्षेत्र के 8 लोकसभा क्षेत्रों में सिर्फ 2 पर भाजपा जीती, जबकि 5 कांग्रेस के खाते में गईं।

कांग्रेस के ग्लैमरस चेहरे, तीन बार के सांसद और युवाओं की राजनीति में भाजपा के लिए परेशानी का सबब बने ज्योतिरादित्य सिंधिया का कैबिनेट मंत्री न बनना चौकाने वाला निर्णय रहा। उनकी वरिष्ठता और अनुभव को देखते हुए यह उम्मीद की जा रही थी कि उन्हें कम से कम स्वतंत्र प्रभार का राज्यमंत्री बनाया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस की अपनी गुटबाजी ने इस मामले में पर्दे के पीछे से कुछ असर जरूर दिखाया है।

रिश्तेदारों से भरी पड़ी है मनमोहन की टीम

नई दिल्ली। बेटे, बेटा, पत्नी ही नहीं ससुर-दामाद की जोड़ी भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की टीम में शामिल है। दो-तीन दिनों की मंथन के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राजनीतिक सचिव अहमद पटेल और वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी ने मंत्रियों की जो सूची राष्ट्रपति को सौंपी उसे देखकर ऐसा ही लगता है कि वो वंशवाद और भाइ-भतिजा वाद से प्रभावित है। कांग्रेस ने 79 में से 60 अपने विश्वसत मंत्रियों पर ही विश्वास किया।

कभी कांग्रेस को चुनौती देकर नाम कमा चुके स्व जितेंद्र प्रसाद के युवराज जितिन प्रसाद भी पिछली बार की तरह राज्यमंत्री बने। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पत्नी

परनीत कौर भी टीम में शामिल हुई। मध्य भारत से स्व माधवराव सिंधिया के पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुभाष यादव के बेटे अरुण यादव राज्यमंत्री बनकर परिवारवाद का झंडा लहराया। वहीं पश्चिम से पूर्व केन्द्रिय मंत्री स्व माधव सिंह सोलंकी के पुत्र भरत सिंह सोलंकी और गुजरात के

पहले पेज से जारी... मनमोहन टीम में...

इनमें फारूख अब्दुल्ला नेशनल कांफ्रेंस और एक राज्यमंत्री तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं। जबकि कांग्रेस की ओर से केवल सलमान खुरशीद ही मंत्री बनाये गये हैं। इसी तरह राज्यवार भी मनमोहन सिंह न्याय नहीं कर पाए हैं। 80 सदस्यीय उनके मंत्रिमंडल में 17 मंत्री तो केवल तमिलनाडु और पं. बंगाल से ही हैं। जबकि आंध्र से जबर्दस्त सीटें मिलने के बावजूद केवल एक केबिनेट मंत्री बनाया गया है। हरियाणा और राजस्थान भी खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। उ.प्र. को भी केवल पांच राज्यमंत्रियों में संतोष करना पड़ा है। राजस्थान में जाटों के बड़े नेता शीशराम ओला को जहां बाहर किया गया है वहीं उ.प्र. में कर्मियों के बड़े नेता बेनी प्रसाद वर्मा को मंत्री नहीं बनाकर नाराज कर दिया गया है। सक्सेस स्टोरी वाले आंध्र, उ.प्र. को जहां कंजूसी मिली हो कर्नाटक में जहां कांग्रेस की किरकिरी हुई पांच पद दिये गये हैं। वीरभद्र सिंह के नाम पर एक सांसद लाने वाले हिमाचल को दो केबिनेट मंत्री मिले हैं वहीं छत्तीसगढ़, गोवा, मिजोरम, सिक्कीम, मणीपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल, नगालैंड, दमनदीव, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान, निकोबार से कोई मंत्री नहीं बनाया गया है।

मुख्यमंत्री रह चुके अमर सिंह चौधरी के पुत्र तुषार भाई चौधरी भी राजनीति में बंशवाद की अलख जगा रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री बसंतदादा पटिल के पौत्र प्रतीक पाटिल भी नेताओं की तीसरी पीढ़ी के प्रतीक चिन्ह बने। एनटी रामाराव की पुत्री पुरंदेश्वरी फिर मंत्रिमंडल में शामिल हुईं। मंत्रिमंडल विस्तार में अधिक

दावेदारी का पेंच लड़ाने वाली द्रमुक के प्रमुख करुणानिधि के बड़े पुत्र एमके अज्ञागिरी और पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्व मुरासोली मारन के पुत्र और करुणानिधि के भतीजे दयानिधि मारन भी मंत्री बने। जीके मूनार के पुत्र जीके वासन भी कैबिनेट स्तर के मंत्री बने। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष की पुत्री और राकांपा की सांसद और इस मंत्रिमंडल की सबसे युवा नेता अगाथा संगमा ने तो हिन्दी में शपथ ग्रहण कर एक नई शुरुआत की। इस तरह मनमोहन सिंह की टीम ने अधिकतर लोग वंशवेलियां हैं। वैसे भी कांग्रेस भारत में वंशवाद और परिवारवाद के लिए जानी जाती है। अब देखना यह है कि युवाओं और अनुभवी लोगों की यह टीम पांच साल में क्या कमाल दिखाती है।

नौकर शाही में फेरबदल पीएम की प्राथमिकताओं में

नई दिल्ली। जून माह के अंत में अनेक आईएएस अफसरों की सेवा निवृत्ति के मद्देनजर नौकरशाही में फेरबदल प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह की प्राथमिकता सूची में शामिल हो गया है। प्रधान मंत्री कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक आधा दर्जन से अधिक मंत्रालयों ने 15 जून तक नए सचिवों की पदस्थापना करने जरूरी है ताकि जो लोग जून अंत या जुलाई में अवकाश ले रहे हैं उनमें प्रभार लेने में दिक्कत न हो।

काम की गति, नियंत्रण, संतुलन से ही मूल्य, चमक और दृष्टि बढ़ती है

सरकार बन गई और उसके प्रधान मनमोहनसिंह ने यह मन भी जाहिर किया कि योग्यता के आधार पर चुने गये मंत्रियों को काम करके बताना होगा। मनमोहन सिंह के यह मजबूत इरादें हैं जो उन्होंने पहली बार जताए हैं। दरअसल सरकार का सरदार इतना मजबूत तो होना ही चाहिए कि वह भय भले न बने लेकिन उसका व्यापक प्रभाव उसके मातहतों पर हो . तब ही सरकार नजर आएगी क्योंकि सरकार का काम सरक-सरक कर चलना नहीं द्रुत गति से आगे बढ़ना है।

गति वही अच्छी होती है जो संतुलित हो, जिससे घटनाओं की संभावना कम हो और मुकाम पर पहुंचने का विश्वास हो। मनमोहनसिंह ने सरकार की ड्रायविंग सीट पर बैठकर पहले ही दिन जो गति का संतुलन जाहिर किया है वह इस बदली हुई सरकार के बदले हुए लक्षण है। अब जरूरी

है कि वे गतिमान रहें और अपने मंत्रियों की दक्षता से राष्ट्र के विकास की गति को नियंत्रण और संतुलन से तेज करें।

नियंत्रण और संतुलन वह कला है जो आपकी दक्षता को प्रतिबिंबित करता है। प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह को इस दक्षता को सिद्ध करने की चुनौती है। वे कैसे और कितना काम कर पाते हैं यह

देश 2009 के आमचुनाव के बाद इसका आकलन भी करेगा। मनमोहन सिंह की द्वितीय पारी का आकलन इस भरोसे का भी होगा कि सोनिया और राहुल गांधी पर किए गए विश्वास के मत का मूल्य कितना है।

मूल्य वस्तु का ही नहीं आचरण का, विचार का, कार्य दक्षता का भी होता है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर है। सबसे बड़े लोकतंत्र के मतदाताओं ने इन मूल्यों में सोनिया और राहुल को बड़ा पाया है और उन्हें बेहतर ढंग से

सरकार चलाने का भरोसा और मजबूती दी है। आज भारतीय राजनीति के ये दोनों ध्रुव सरकारी सितारों की जमात से दूर हैं फिर भी उनकी चमक सरकारी सौर मंडल पर है। यह उसी भरोसे और मजबूती की चमक है जो उन्हें जनादेश 2009 से मिली है। इसलिए उनकी भी यह जवाबदारी है कि वे सरकार से बाहर रहकर भी इस चमक को बनाए रखें।

चमक का तत्व चमकदार और साफ-सुथरा रहना है पर साफ-सफाई का कोई तत्व नहीं होता साफ-सफाई तो बनाए रखना होती है। मनमोहनसिंह सरकार में साफ-सफाई और चमकदारी बने रहे इसका दायित्व भी सोनिया और राहुल का है। सरकार कैसे काम करे यह जरूर मनमोहनसिंह देखें लेकिन किस तरह काम कर रही है इसे सोनिया

और राहुल गांधी को देखना ही होगा। उस पर दृष्टि रखना ही होगी।

दृष्टि वही है जो आप देख रहे हैं पर दृष्टि वह भी है जो आप विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं और उसे योजनाबद्ध कर रहे हैं। इतना होने पर बस आपको क्रियांवयन का प्रयास करना होता है। यह हो रहा है कि नहीं इसे देखने के लिए साफ और स्वच्छ कांच की जरूरत है। उस कांच की धूल, परत और गंदगी साफ होते रहना चाहिए। यह जवाबदारी जनादेश 2009 से सोनिया और राहुल गांधी को मिली है इसे निभाना ही उनका दायित्व है।

सरकार की गति, नियंत्रण, संतुलन उसकी मूल्य, चमक और दृष्टि के लक्षण कैसे होंगे यह आने वाले दिनों में सरकार के कामकाज से दिखेंगे क्योंकि काम की गति, नियंत्रण, संतुलन से ही मूल्य, चमक और दृष्टि बढ़ती है।

चक्रम

सुरेन्द्र बंसल